भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2616

मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

डेटा केंद्र परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2616. श्री प्रवीण पटेलः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
कैप्टन बृजेश चौटाः
श्री दर्शन सिंह चौधरीः
श्री विष्णु दयाल रामः
श्री यदुवीर वाडियारः
श्री पुट्टा महेश कुमारः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री अनिल फिरोजियाः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2029-30 तक भारत में डेटा केंद्र परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) कितना है;

(ख) प्रमुख हाइपरस्केलर और घरेलू ऑपरेटरों द्वारा कुल एफडीआई योगदान कितना है;

(ग) क्या सरकार के किसी प्रस्ताव में कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिलों को विशेष रूप से शामिल किया गया है, क्योंकि यह एक प्रमुख पत्तन के निकट है और उसके पास विश्वसनीय विद्युत अवसंरचना उपलब्ध है और यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों के अनुमोदन, कार्य की शुरुआत और संभावित परिचालन की समयसीमा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने डेटा केंद्र क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रभावित करने वाली प्रमुख नीतिगत बाधाओं की पहचान की है और यदि हां, तो सरकार द्वारा कर संबंधी मंजूरी, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन और अन्य क्षेत्र विशिष्ट अनुमतियों को सुव्यवस्थित करने के लिए किए जा रहे उपाय क्या हैं;

(ङ) उन प्रमुख कंपनियों की सूची से संबंधित ब्यौरा क्या है, जिन्होंने विगत पांच वर्षों के दौरान विशेषकर आंध्र प्रदेश में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए भारत में निवेश किया है; और

(च) उक्त कंपनियों और घरेलू ऑपरेटरों द्वारा किया गया कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): डीपीआईआईटी द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का अंतर्वाह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, बाजार का आकार, अवसंरचना, राजनीतिक एवं सामान्य निवेश वातावरण और साथ ही व्यापक आर्थिक स्थिरता और विदेशी निवेशकों के निवेश संबंधी निर्णय।

(ग): कर्नाटक डाटा सेंटर (डीसी) नीति 2022-2027, बेंगलुरु क्षेत्र के बाहर, मंगलुरु और मैसूरु सहित दक्षिण कन्नड़ जिले के भौगोलिक क्षेत्रों में डाटा सेंटर कंपनियों को डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।

(घ): डाटा सेंटर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह सहित, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने निवेशक अनुकूल नीति तैयार की है। भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या फा. सं. 13/1/2017-आईएनएफ दिनांक 11 अक्तूबर 2022 के माध्यम से अवसंरचना उप-क्षेत्रों की हारमोनाइजेशन मास्टर लिस्ट में डाटा सेंटरों को शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, भारत को एक आकर्षक और निवेशक अनुकूल गंतव्य बनाए रखने के लिए, सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की निरंतर समीक्षा करती है और शीर्ष उद्योग मंडलों, संघों, उद्योग/समूहों के प्रतिनिधियों और अन्य संगठनों सहित हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद, उनके विचारों/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर इसमें परिवर्तन करती है।

(ङ) और (च): डाटा सेंटर के संबंध में इस प्रकार के कोई राज्यवार आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

*****